एस.एस. कांग जे. के समक्ष

दीप चंद, -याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, -प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या 8563, 1987

4 दिसंबर 1987.

*हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम,*1978—नियम 74 एवं 85(1)(डी) एवं (IV)-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226 एवं 329—नगरपालिकाचुनाव-प्राधिकरण चुनाव कार्यवाही को रद्द कर रहा है और पुनर्मतदान का आदेश दे रहा है-आदेश-क्या चुनावी प्रक्रिया में एक कदम है-आदेश की वैधता-क्या वह अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में मध्यवर्ती चरण में प्रश्न पूछ सकता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि यह लोकतांत्रिक राजनीति का सार है कि विभिन्न वैधानिक कार्य करने वाले निर्वाचित निकायों के चुनाव शीघ्रता से और निर्धारित समय सीमा के भीतर होने चाहिए। चुनाव किसी भी मध्यवर्ती चरण में नहीं रोका जाना चाहिए। चुनाव संबंधी विवादों को नतीजे आने के बाद सुलझने का इंतजार करना पड़ता है। उस मामले के लिए उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में वैकल्पिक उद्यमों को चल रही चुनावी प्रक्रिया को रोकने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 329 में निहित है। चुनाव को अनावश्यक रूप से लंबा या बाधित नहीं किया जाना चाहिए। विधायी निकायों में मतदाताओं के लिए उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में गति और तत्परता ही कला में इस सिद्धांत के अवतार का वास्तविक कारण है। संविधान के 329 और बाद में हरियाणा नगरपालिका चुनाव नियम, 1978 के नियम 74 में। -

(पैरा 7).

अभिनिर्धारित किया गया कि मतदान रद्द करने और पुनर्मतदान का निर्देश देने का आदेश चुनावी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह चुनाव के दौरान चुनाव पूरा करने के उद्देश्य से पारित एक आदेश है। इसे केवल परिणाम घोषित होने के बाद ही चुनौती दी जा सकती है और वह भी चुनाव याचिका के माध्यम से। पुनर्मतदान के साथ-साथ मतदान रद्द करने को चुनौती देने वाली रिट याचिका चुनाव प्रक्रिया में एक कदम पर सवाल उठाने के समान है और यह उचित उपाय नहीं है।

(पैरा 11).

बी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951 का XLIII) - धारा 153 - हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1978 - नियम 74 - धारा 153 के साथ सममूल्य पर नियम 74 - परिणाम की घोषणा के बाद चुनाव याचिका के माध्यम से उपाय - प्रतिनिधित्व अधिनियम के ऐसे नियम - क्या नगरपालिका चुनावों पर लागू होता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि हरियाणा नगरपालिका चुनाव नियम, 1978 के नियम 74 की भाषा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 153 के प्रावधानों के समान है। इसलिए यह

सिद्धांत कि चुनाव याचिका केवल चुनाव समाप्त होने के बाद ही प्रस्तुत की जा सकती है, समान रूप से आकर्षित है नगरपालिका चुनावों से उत्पन्न होने वाले चुनावी विवादों के लिए।

(पैरा 8).

लेख के तहत याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में प्रार्थना की गई है कि निम्नलिखित राहत दी जाए: -

(i) सर्टिओरारी *की प्रकृति में एक रिट* विवादित आदेश के संबंध में प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के रिकॉर्ड को मंगाने के लिए की रिट जारी की जाए और उसके अवलोकन के बाद, उसने जिस आदेश को रद्द कर दिया है;

*(ii) उत्तरदाताओं को निर्देशित करने वाले परमादेश की प्रकृति की एक रिट।*1 और 2 वार्ड संख्या 33 के बूथ संख्या 86 और 87 पर सुबह 8 बजे के बीच हुए मतदान को नहीं माना जाएगा। और मतदान को निलंबित करने का समय और शून्य के रूप में और उन मतदाताओं के संबंध में आगे मतदान का आदेश देने के लिए जिन्होंने सुबह 8.00 बजे के बीच अपने वोट नहीं डाले थे। और निलंबन का समय;

*(iii) कोई अन्य उपयुक्त लेखक्य*ह, आदेश या निर्देश जो माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, जारी किया जाए;

*(iv) उत्तरदाताओं की संख्या पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया जाए।*1 और 2 को इस रिट याचिका का निर्णय होने तक हिसार नगर समिति के वार्ड नंबर 33 में पुनर्मतदान कराने से; और

(v) याचिकाकर्ता को याचिका *की लागत* की अनुमति दी जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से आनंद स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता (श्री जसवन्त जैन, उनके साथ अधिवक्ता)।

एस.वी.राठी. उत्तरदाताओं 1 और 2 के लिए ए.जी. (हरियाणा)

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक भान (मैसर्स ए.के. मित्तल, पुनित जिंदल और आर.के. गर्ग, उनके साथ वकील)

.

निर्णय

सुखदेव सिंह कंग, जे.—

(1) फोरेंसिक मुद्दों का समुदाय और दो रिट याचिकाओं (सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 8563 और 8765, 1987) में तथ्य स्थितियों में समानता एक सामान्य निर्णय की मांग करती है।

(2) कंकालीय तथ्यों का संक्षिप्त संदर्भ एक प्रारंभिक आवश्यकता है।

(3) म्यूनिसिपल कमेटी हिसार के चुनाव 30 अक्टूबर 1987 को हुए। दीप चंद, याचिकाकर्ता सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 8563 सन् 1987 एवं छत्तर पाल, याचिकाकर्ता सी.डब्लू.पी. 1987 के क्रमांक 8765 क्रमशः वार्ड क्रमांक 33 और 25 से उम्मीदवार थे। दोपहर के भोजन के बाद तक मतदान केंद्रों पर मतदान जारी रहा जब मतदान केंद्रों के पास और सामने हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुईं। इस संबंध में पुलिस में आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। दोनों वार्डों के पीठासीन अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उपायुक्त, हिसार ने चुनाव कार्यवाही रद्द कर दी और इन वार्डों के लिए पुनर्मतदान का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने 30 अक्टूबर, 1987 को हुए मतदान को रद्द करने और पुनर्मतदान के निर्देशों की आलोचना की है। उत्तरदाताओं ने रिट याचिकाओं का विरोध किया है और तथ्यात्मक दावों का खंडन किया है।

(4) रिट याचिकाओं की सुनवाई में, उत्तरदाताओं की ओर से एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि चुनाव कार्यवाही को रद्द करने और पुनर्मतदान का आदेश देने वाला आदेश चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के कदम थे। इनका निर्माण चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया है. चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उसे किसी भी मध्यवर्ती चरण में नहीं रोका जाना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद चुनाव याचिका दायर करके अपनी शिकायतों का निवारण कर सकते हैं। आपत्ति में दम है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

(5) हरियाणा नगरपालिका चुनाव नियम, 1978 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) अन्य बातों के साथ-साथ, मतदाता सूची तैयार करने, नगरपालिका समितियों के चुनाव कराने, उनकी सदस्यता के लिए अयोग्यताएं, चुनाव की घोषणा के लिए प्रक्रिया अधिनियमित करता है। परिणाम, चुनाव विवादों का निर्धारण। नियम राज्य में नगरपालिका समितियों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों का ध्यान रखते हैं। इन चुनावों को कराने का दायित्व नियमानुसार उपायुक्त को सौंपा गया है। नियम 19 के तहत, उपायुक्त एक समिति के चुनाव के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेगा। वह एक रिटर्निंग अधिकारी को नामित या नामांकित करेगा, नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख, उसकी जांच, मतदान की तारीखें और मतदान के परिणाम की घोषणा तय करेगा। नियम 58 उपायुक्त को किसी भी स्टेशन पर मतदान को शून्य घोषित करने और उस विशेष मतदान केंद्र के लिए नए सिरे से मतदान कराने के लिए एक दिन तय करने की शक्ति प्रदान करता है। नियम 73 से 88 चुनावी विवादों के समाधान से संबंधित प्रावधानों से संबंधित हैं। वे, अन्य बातों के अलावा, भ्रष्ट आचरण को परिभाषित करते हैं,

चुनाव याचिका दायर करने का प्रावधान करते हैं, चुनाव याचिका के निपटान के लिए आयोग की नियुक्ति करते हैं, विवादों की जांच के लिए प्रक्रिया तैयार करते हैं और निर्धारित करते हैं और चुनाव को शून्य घोषित करने के लिए आधार बनाते हैं। नियम 74, जो प्रारंभिक आपत्ति के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, पढ़ता है: -

> "इन नियमों के अनुसार चुनाव याचिका के अलावा किसी भी चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।"

नियम 85(एल)(डी)(iv) में कहा गया है कि यदि आयोग की राय है कि चुनाव के परिणाम, जहां तक इसका संबंध किसी निर्वाचित उम्मीदवार से है, चुनाव की प्रक्रिया में किसी भी भौतिक अनियमितता से प्रभावित हुआ है। चुनाव के बाद, आयोग निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित कर देगा।

(6) पार्टियों के विद्वान वकील इस बात पर सहमत हैं कि रिट याचिकाओं में शामिल आरोप चुनाव को रद्द करने का आधार बनते हैं, जैसा कि नियम 85 में बताया गया है।

(7) यह लोकतांत्रिक राजनीति का सार है कि विभिन्न वैधानिक कार्य करने वाले निर्वाचित निकायों के चुनाव शीघ्रता से और निर्धारित समय सीमा के भीतर होने चाहिए। चुनाव किसी भी मध्यवर्ती चरण में नहीं रोका जाना चाहिए। चुनावों से संबंधित विवादों को परिणाम की घोषणा के बाद उनके समाधान की प्रतीक्षा करनी होगी, उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत में इस मामले के लिए वैकल्पिक उद्यमों को चल रही चुनावी प्रक्रिया को रोकने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 329 में निहित है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ आदेश दिया गया है कि संविधान में किसी भी बात के बावजूद, चुनाव याचिका के अलावा, संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद चुनाव विवादों को स्थगित करने का कारण यह है कि इन निकायों में चुनाव अनावश्यक रूप से लंबा न खिंचे या बाधित न हो। विधायी निकायों में मतदाताओं के लिए उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में गति और तत्परता ही इस सिद्धांत को संविधान के अनुच्छेद 329 और बाद में नियम 74 में शामिल करने का वास्तविक कारण है। इस सिद्धांत को तीसरे वर्ष में अंतिम न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई थी। ***एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर, नामोक्कल निर्वाचन क्षेत्र***[1] में यह देखा गया था:

> "लोकतांत्रिक देशों में विधायिकाओं को जो महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए, ऐसा करना पड़ता हैयह सर्व प्रथम महत्व का विषय माना गया है कि चुनाव यथाशीघ्र समय-सारणी के अनुसार संपन्न करा लिए जाएं तथा सभी विवादास्पद मामले तथा चुनाव से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को चुनाव समाप्त होने तक के लिए

[1] A.I.R. 1952 S.C. 64

स्थगित कर दिया जाए ताकि चुनाव की कार्यवाही आगे न बढ़ सके। अनावश्यक रूप से मंद या लम्बा होना।

इस सिद्धांत के अनुरूप, इस देश के साथ-साथ इंग्लैंड में भी चुनाव कानून की योजना यह है कि ऐसी किसी भी चीज़ को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जो 'चुनाव' को प्रभावित नहीं करती है, और यदि चुनाव जारी रहने के दौरान कोई अनियमितता की जाती है और वे उस श्रेणी या वर्ग से संबंधित हैं, जो उस कानून के तहत, जिसके द्वारा चुनाव शासित होते हैं, 'चुनाव' को ख़राब करने का प्रभाव होगा और प्रभावित व्यक्ति को इसे प्रश्न में बुलाने में सक्षम करेगा, उन्हें एक विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष लाया जाना चाहिए चुनाव याचिका का मतलब है और जब चुनाव चल रहा हो तो उसे किसी भी न्यायालय के समक्ष विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।"

(8) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के विभिन्न प्रावधानों की जांच और विश्लेषण करने के बाद, उनके आधिपत्य ने बताया था कि यह उचित निष्कर्ष होगा कि अधिनियम चुनाव समाप्त होने के बाद केवल एक चुनाव याचिका प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है, और कोई नहीं था। किसी भी मध्यवर्ती चरण में उपचार प्रदान किया जाता है। जब भी हम किसी लोकतांत्रिक देश में चुनाव की बात करते हैं तो "चुनाव" शब्द एक उम्मीदवार को वापस करने के लिए अपनाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया को दर्शाता है। चूँकि नियम 74 की भाषा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के समान है, जो शीर्ष न्यायालय के समक्ष निर्माण के लिए आया था, ऊपर दिए गए सिद्धांत नगरपालिका चुनावों से उत्पन्न होने वाले चुनावी विवादों पर समान रूप से आकर्षित होते हैं।

(9) यहां तक कि नियम 74 जैसे स्पष्ट और स्पष्ट प्रावधानों के अभाव में भी, शीर्ष न्यायालय ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के संदर्भ में, ***नारिंदु मल और अन्य बनाम हीरा मल और अन्य***[2] में समान सिद्धांत लागू किया, जिसमें यह अवलोकित किया गया :

"नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष के पद के चुनाव को केवल यू.पी. नगर पालिका अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चुनौती दी जा सकती है और यह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत चुनाव याचिका के माध्यम से है, किसी अन्य तरीके से नहीं।" . चुनाव याचिका चुनाव समाप्त होने के बाद प्रस्तुत की जानी है और किसी भी मध्यवर्ती चरण में कोई उपाय प्रदान नहीं किया गया है। धारा 438 की उपधारा (2) में उल्लिखित तीन आधारों में से केवल एक या अधिक आधार पर ही चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है। वर्तमान मामले में एकमात्र आधार जिसके आधार पर रिट क्षेत्राधिकार में राष्ट्रपति के चुनाव पर सवाल उठाया गया था। उच्च न्यायालय का कहना था कि अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 6 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया

[2] A.I.R. 1975 S.C.2140

गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की वैधता तय करने का अधिकार क्षेत्र विशेष रूप से जिला न्यायाधीश को दिया गया है। इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के लिए चुनाव को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। चुनाव को रद्द करने में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से गलती की क्योंकि उसने इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या चुनाव के परिणाम संबंधित नियमों का अनुपालन न करने से प्रभावित हुए थे। किसी भी मामले में यह जिला न्यायाधीश के विशेष अधिकार क्षेत्र का मामला है।

(10) सवाल यह उठता है कि क्या चुनाव की कार्यवाही को रद्द करने का आदेश और नगरपालिका समिति में पुनर्मतदान का आदेश देना चुनाव की प्रक्रिया में एक कदम है। इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने ***मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य***[3] के मामले में दिया है, यह कहा गया है:

> "चुनाव में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 14 के तहत अधिसूचना जारी करने से लेकर अधिनियम की धारा 66 के तहत परिणाम की घोषणा तक की पूरी प्रक्रिया शामिल है। जब कोई मतदान जो पहले ही हो चुका है, रद्द कर दिया गया है और नए सिरे से मतदान का आदेश दिया गया है, तो संशोधित तिथि के साथ आदेश चुनावी प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में पारित किया जाता है। जब चुनाव आयोग ने अपनी अधिसूचना में संशोधन किया और नए सिरे से मतदान का आदेश देकर चुनाव पूरा करने का समय बढ़ाया, तो यह 'चुनाव' की प्रक्रिया के दौरान एक आदेश है। भले ही यह गलत आदेश हो, फिर भी यह आरोपित सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश नहीं रह जाताचुनाव संपन्न कराने के लक्ष्य और उद्देश्य के साथ चुनाव का संचालन। यद्यपि यह हमेशा निर्णायक नहीं होता है, जहां संविधान के अनुच्छेद 324(1) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 153 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, ऐसा आदेश, जैसा कि यह करता है, से संबंधित है। अधिनियम के तहत चुनाव याचिका के अलावा चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। यदि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान, मध्यवर्ती या अंतिम चरण में, पूरे मतदान को गलत तरीके से रद्द कर दिया गया है और नए सिरे से मतदान का गलत आदेश दिया गया है, तो यह एक ऐसा मामला है जो नए मतदान के आधार पर परिणाम घोषित होने के बाद उत्तेजित हो सकता है। , कानून के अनुसार चुनाव याचिका के माध्यम से उचित मंच पर चुनाव पर सवाल उठाकर। तब, याचिकाकर्ता के पास चुनावी प्रक्रिया के हर कदम और पिछले चुनाव को रद्द करने सहित चुनाव की प्रक्रिया में पारित किए गए हर आदेश पर सवाल उठाने का उपाय होगा।
>
> "अनुच्छेद 226 के तहत कैच-ऑल क्षेत्राधिकार पुनर्मतदान के साथ एकीकृत रद्द करने के

[3] A.I.R. 1978 S.C. 851

निर्देश की शुद्धता, वैधता या अन्यथा पर विचार नहीं कर सकता है। क्योंकि, इस तरह के पुनर्मतदान का मुख्य उद्देश्य एक विस्तृत मतदान प्रक्रिया को बहाल करना और पुनर्मतदान के मुक्ति प्रयास के माध्यम से इसे पूरा करना है। पुनर्मतदान के साथ रद्दीकरण को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका 'चुनाव' में एक कदम पर सवाल उठाने के समान है और इसलिए इसे अनुच्छेद 329 (बी) द्वारा वर्जित किया गया है।

(11) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि चुनाव में चुनाव कार्यक्रम जारी करने से लेकर चुनाव के परिणाम की घोषणा तक की पूरी प्रक्रिया शामिल है और मतदान रद्द करने और पुनर्मतदान का निर्देश देने का आदेश चुनावी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह चुनाव के दौरान चुनाव पूरा करने के उद्देश्य से पारित एक आदेश है। इसे केवल परिणाम घोषित होने के बाद ही चुनौती दी जा सकती है और वह भी चुनाव याचिका के माध्यम से। पुनर्मतदान के साथ-साथ मतदान रद्द करने को चुनौती देने वाली रिट याचिका चुनाव में एक कदम पर सवाल उठाने के बराबर है, यह उचित उपाय नहीं है।

(12) नतीजतन, प्रारंभिक आपत्ति को बरकरार रखा जाता है और रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि रिट याचिकाएं तकनीकी आधार पर खारिज कर दी गई हैं और ऐसा नहीं थाविवाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त करने का इरादा। फैसले से निकाले जा सकने वाले गुणों पर कोई भी प्रतिबिंब पूरी तरह से अनपेक्षित था और आयोग के दिमाग को प्रभावित नहीं करेगा, जिसे चुनाव विवाद से जब्त किया जा सकता है। कोई लागत नहीं.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

विनीत कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा